तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और जांच का परिणाम क्या है। इस प्रश्न को पूछते हुये मैं यह भी आश्वासन चाहता हूं कि हर चुनाव के पहले चीनी के दाम बढ़ जाते हैं। तो क्या सरकार यह आश्वासन देंगी कि इस बार चुनाव के पहले चीनी के दाम नहीं बढ़ेंगे।

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, कोई भी अनियमितता नहीं हुई है तो फिर जांच का प्रश्न कहां उठता है।

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति महोदय, (च) का कोई उत्तर नहीं दिया **(व्यवधान)**

श्री शिवचरण सिंह : सभापति महोदय, चीनी मिलों के लाइसेंस के बारे में मैं प्रधानमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं। चीनी मिलों को लगाने का लाइसेंस देते समय आपने 25–30–50 किलोमीटर की परिधि की पाबन्दी रखी है। चीनी मिलों वाले इस प्रणाली के माध्यम से किसानों का गन्ना कम दाम पर और उधार खरीदने के लिये उनको मजबूर करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस लाइसेंस सिस्टम को समाप्त करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्रीमती कृष्णा साही : इससे यह सवाल नहीं उठता।

Import of Urea

542. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to import 1.5 mt of urea for the ensuring kharif season this year as reported in the Economic Times dated 8th April, 1994;

(b) if so, the reasons therefor indicating urea imports last year, projected annual demand during the current year, actual availability of indigenous fertilizers, foreign exchange availability positions this year, and allocation made for subsidising imported nitrogenous fertilizers in the Budget for 1994-95; and

(c) whether the differences among the Ministry of Finance, Ministry of Chemicals and Fertilizers and the Ministry of Agriculture over the actual demand estimates have been resolved and if so, at what stage the matter stands at present after taking into account the recommendations of the Review Committee?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) 28.40 lakh tonnes of urea were imported during 1993-94. Availability of indigenous urea during 1994-95 is estimated to be of the order of 155 lakh tonnes. Adequate foreign exchange is available for fertilizer imports. Budget for 1994-95 contains a provision of Rs. 500 crores for subsidy on imported fertilizers.

Urea imports are effected to bridge the gap between demand and availability. It will not be in public interest to disclose in advance, information regarding imports.

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं अपना पूरक प्रश्न पूछूं, उसके पहले आपका संरक्षण प्राप्त करते हुए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खाद का आयात और उसकी सप्लाई, क्या यह भी कोई पब्लिक इंट्रेस्ट में छिपाने वाली कोई बात है? मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि पब्लिक इंट्रेस्ट में नहीं होगा कि इस प्रकार की सूचनाएं दी जाएं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की सूचनाएं जिनके द्वारा आप इम्पोर्ट करेंगे, इन्क्वायरीज़ फ्लोट करेंगे, मार्केट में जाएंगे, शिपमेंट बुक करेंगे शिप आएंगे और जाएंगे, यह सारी, प्रक्रिया जब होगी तो क्या यह पब्लिक इंट्रेस्ट में छिपाने वाली प्रक्रिया में से है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की इतनी लम्बी कार्यवाही जिसमें हो, वह

पब्लिक इंट्रेस्ट में छिपी रह सकती है तथा पार्लियामेंट से भी आप छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री राम लखन सिंह यादव : सभापति महोदय, माननीय सदस्य अगर प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति महोदय से मैंने निवेदन किया है कि क्या यह उचित है। यह मेरा पूरक प्रश्न नहीं है।

श्री राम लखन सिंह यादव : सभापति महोदय, कुछ यूरिया का देश में उत्पादन होता है और कुछ हम बाहर से मंगा कर आपूर्ति करते है। बाहर से मंगाने की एक प्रक्रिया है और वह इटरनेशनल मार्किट से संबंधित है। ऐसी स्थिति में पब्लिक इंट्रेस्ट में है इस बात को जब तक हम खत्म न कर लें, ले नहीं लें, तब तक यह नहीं खुले अन्यथा इसके भाव पर असर पड़ जाता है। इसलिए किसानों के इंट्रेस्ट में है, देश के इंट्रेस्ट में है कि जब तक उसका फाइनल डिसिज़न न हो जाए, हम मंगा नहीं लें तब इसका भाव क्या होगा, कितना मंगाना होगा, क्या करना होगा, इसका भेद नहीं खोला जाए। ऐसा मैं मानता हूं।

श्री रामदास अग्रवाल : मेरा पहला प्रश्न है। वह तो मैंने आपके माध्यम से जानकारी मांगी थी **(व्यवधान)**

DR. BIPLAB DASGUPTA: Why can't you give estimates?

MR. CHAIRMAN: He has answered the question.

श्री सिकन्दर बख्त : इसमें पब्लिक इंट्रेस्ट का पहलू क्या है, यह बताएं। कमाल हो गया।

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

श्री राम लखन सिंह यादव : सभापति महोदय, मैंने अभी बतलाया कि अगर मान लीजिये आज हम कोई चीज़ खरीदते हैं, इस भाव में इतनी खरीदेंगे तुरंत उसका मार्केट पर असर पड़ जाएगा यहां के व्यापारी भी बाहर के इंटरनेशनल कम्पीटीशन में आते हैं। जिस देश से हम खरीदते हैं उस पर भी इसका असर पड़ जाएगा। इससे हम को घाटा हो जाएगा। इसलिए पब्लिक इंट्रेस्ट में है कि इस बात को नहीं खोला जाए।

श्री रामदास अग्रवाल : मेरा पहला प्रश्न यह है..

MR. CHAIRMAN: First question he has answered. Please ask your second supplementary.

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न है मंत्री जी से कि वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और फर्टिलाइज़र मंत्रालय, इन तीनों के बीच में यह बड़ी बहस हुई थी कि कितना यूरिया भारतवर्ष की आवश्यकता के लिए इम्पोर्ट करना चाहिये। कृषि मंत्रालय ने आपसे यह कहा था, सुझाव दिया था कि 4.5 मिलियन टन की आवश्यकता है। इन तीनों मंत्रालयों के विवाद में यह मसला कई दिनों, कई महीनों तक टलता रहा। उसके कारण निर्णय केवल इतना ही हुआ है कि 1.5 मिलियन टन आयात किया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं, मेरे सप्लीमेंटरी का पहला भाग है, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि तीनों मंत्रालयों में यह विवाद क्यों पैदा हुआ? क्योंकि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मेरे प्रश्न का "सी" भाग था उसका उत्तर आपने अपने जवाब में बिल्कुल नहीं दिया है। मैंने यह जो कहा था कि तीनों मंत्रालयों में विवाद है इस बात का आपने उत्तर नहीं दिया है तो मैं यह मानूं कि आप इसको स्वीकार करते हैं इसलिए उत्तर नहीं दे रहे हैं या आप अस्वीकार करते हैं इसलिए उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री रामलखन सिंह यादव : सभापति महोदय, रामायण की एक चौपाई है, "जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत

देखी तिन तैसी" तो हमारे माननीय सदस्य को हमेशा गवर्नमेंट में डिफरेंसेज ही मालूम पड़ते हैं। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि न तो कृषि विभाग से, न तो फाइनेंस से और हमारे विभाग से किसी विषय पर या इस मामले को लेकर आज तक कभी डिफरेंसेज हुए हैं। विचार होता है, आपस में अफसर बैठते हैं। उसके लिए एक कमेटी है, और जितने फैसले अभी तक हुए हैं और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो फैसल होंगे, सर्वसम्मति से होंगे। इसलिए आपको अधिक कोई तकलीफ करने की या उठाने की आवश्यकता है। इसलिए माइड की एक्सरसाइज ज्यादा मत कीजिए।

श्री रामदास अग्रवाल : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है, क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर कारपोरेशन... **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: I am afraid, you have already put it as a second part of your question.

श्री रामदास अग्रवाल : फोर्थ नहीं है केवल दूसरा भाग है मेरे प्रश्न का। क्या यह सच है कि आर.सी.एफ.— राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड का प्रोडक्शन गत वर्ष 93–94 में केवल 17.5 लाख टन्स हुआ जबकि उसको गैस की सप्लाई यदि आप पूरी और बराबर देते तो उनका प्रोडेक्शन 18.7 लाख टन हो सकता था... **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: You did not say earlier it was 'part one' and 'part two' questions.

श्री रामदास अग्रवाल : और आप फारेन एक्सचेंज बचा सकते थे केवल गैस सप्लाई को देकर, तो आखिर गैस सप्लाई क्यों नहीं हो पाई, इसको तो कम से कम उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री रामलखन सिंह यादव : 91 से 94 के दौरान जो हमारी उपज हुई है यह पहले की अपेक्षा अधिक हुई है इसलिए कम होने का प्रश्न नहीं उठता। खास किसी फैक्ट्री में किसी कारण से किसी वक्त में व्यवधान पैदा हो गया हो तो उसके लिए अलग क्वेश्चन चाहिए।

श्री रामदास अग्रवाल : आपके मंत्रालय में है यह... **(व्यवधान)**

श्री राम लखन सिंह यादव : सभी मंत्रालयों के जवाब आपकी ही सप्लीमेंट्री में दें ऐसा सभव नहीं है।

श्री वीरेन्द्र कटारिया : यूरिया का इम्पोर्ट जितना प्रोडक्शन और खपत होती है उसके मुताबिक किया जाता है। पिछले साल जितना अंदाजा प्रोडक्शन का था इससे 10 लाख टन यूरिया की प्रोडक्शन कम हुई थी। 1994–95 में यूरिया की प्रोडक्शन का अंदाजा 155 लाख मीट्रिक टन मंत्री साहब ने अपने जवाब में दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस अदाजे का आधार क्या है और क्या गारटी है कि पिछले साल की तरह इस साल भी अंदाज से कम प्रोडक्शन न हो। क्या यह सच है कि इस लेस प्रोडक्शन की वजह गैस बेस्ड प्लांट को पूरी गैस न देना है? मैं मंत्री साहब से यह भी पूछना चाहता हूं कि हम कब तक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में खुद कफील हो जायेंगे?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): Mr. Chairman, Sir, the first point that I would like to make is that our production of nitrogenous fertilizer has been increasing steadily year after year except last year. We had a small problem because of some shortfall due to problems of availability of gas. There are competing claims on our limited gas from the power sector, from the steel sector, from petro-chemicals and there was also some mechanical failure, not in our public sector units but in the Indo-Gulf Fertilizer Corporation which is a major fertilizer company in the private sector. So, that is the position. Our indigenous production is continuously increasing. Now we are also having off-

shore ventures. This year we have already a joint venture with Senegal. In a couple of years we will have joint ventures in Jordan. That is also a SPIC in the private sector. We are negotiating with the private sector and the public sector and other joint ventures abroad, off-shore in Iran, in Qatar, in Brunei and in other places. So, we are working in that direction.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Mr. Chairman, Sir, if what the hon. Minister has said is true, why is it in 1992-93 we had imported 18 lakh tonnes of urea and 28 lakh tonnes of urea in 1993-94? The import is on the increasing side in spite of what the hon. Minister claimed. I would like to know what exactly the demand-supply gap is for 1994-95. Even if this information is not given in this House, from the FAI's surveys, it is known. I may even venture to tell you that by the Ninth Plan, there is going to be an anticipated demand-supply gap of 72 lakh tonnes of urea. I would like to be contradicted on that.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, the hon. Minister has very rightly pointed out... (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER: Hon. Member.

SHRI EDUARDO FALEIRO: The Minister has very rightly pointed out that it is not in public interest. He has also disclosed why it is not in public interest. It is an international market. India and China are the major players in this market. If we say how much we are going to buy, the supply will change accordingly. Hon. Members who know anything of economics will understand that the prices will be fixed accordingly. Therefore, the reply to that question is like that.

The other point that the hon. Member wants to know is why we are showing increased imports of urea. The reason is, in that particular year, in 1991 and thereabouts, there was a drought. And there were additional stocks remaining for the next year And, therefore, the demand for the next year is reduced. Secondly, the JPC report implementation policy led to the purchase of phosphatic and potassic fertilizers, thereby increasing the purchase of urea. While the reduction in price of urea by 10 per cent was made in furtherance of the JPC recommendations, the prices of phosphates and potassium were decontrolled. That imbalance has been discussed in this House.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: That is my question. The demand of urea is increasing for whatever reason the hon. Minister might say. But our production is not matching that demand. That is the question. How are you going to see that the production matches the demand? How are you going to fill the gap? Why are the eastern region plants in Durgapur, Barauni, etc. shut down? How are you going to mop up resources for this? That is the point. The revival plan for these plants is lying there for the last one and a half years. The Government has not given any scheme for these plants.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister is answering. Please listen to him.

श्री राम लखन यादव : महोदय, यह बात सही है कि जितनी डिमान्ड हमारे इस देश में किसानों की है उतना पूर्ण रूप से हमारे यहां अभी उत्पादन नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो 1991-92, 1992-93, 1993-94 में हम कोई 128 से 131 लाख टन तक हमेशा बढ़ते गए है। लगभग 9.6 परसेंट अधिक हमारा यहां से बराबर उत्पादन बढ़ता गया है और 1994-95 का अनुमान है कि बढ़कर 145.17 लाख टन हो जाएगा और इससे हम बढ़ते जा रहे है। इसके अलावा अभी अपने देश में जो प्राइवेट लोग चला रहे है उनकी भी क्षमता बढ़ रही है और खास तौर से 3 देशों में हम अपनी फैक्ट्रीज कायम

कर रहे हैं जहां गैस और खनिज पदार्थ, रॉ-मैटीरियल वहां उपलब्ध है सब के सब जितना वहां उत्पादन होगा उस देश में एक छटांक भी नहीं रहेगा पूरा उत्पादन हमारे देश में आ जाएगा। इस तरह से अभी हमारी जितनी आवश्यकता है एक-दो साल के अंदर जितना चाहिए उतना तो हम देंगे ही, हो सकता है कि अधिक भी हो जाए इससे हम रोज बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं।

Bird menace at IGIA

*543. SYED SIBTEY RAZI:†
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether incidents of birds hitting the Air India aircraft at the Indira Gandhi International Airport are increasing rapidly;

(b) if so, the details thereof in chronological order from 1st January 1994 to 18th April, 1994;

(c) whether such incidents are also increasing at other air bases of the country;

(d) if so, the details thereof State and Union Territory-wise, from 1st January, 1993 to 18th April, 1994;

(e) whether such incidents are threatening he safety of air passengers seriously;

(f) whether Government propose to take some measures promptly; and

(g) if so, the details thereof and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (g) A statement is laid on the Table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by Syed Sibtey Razi.

Statement

(a) No, Sir.

(b) 13.1.94, Air India B-747 aircraft after take off from IGI Airport was hit by a bird causing damage to No. 1 engine. In the second incident on 15.4.94, the No. 2 engine of an Air India aircraft B-747 was damaged after a bird hit.

(c) The number of bird hits at airports all over India has decreased from 189 in 1986 to 128 in 1993.

(d) the requisite information is furnished in the Statement-I (*See* below).

(e) Yes, Sir.

(f) and (g) The following measures have been taken to reduce the incidence of bird-hits to aircraft in and around airports:—

(i) Airfield Environment Management Committees have been established at airports to monitor the implementation of measures to control zird menace.

(ii) Officials of the Directorate of General of Civil Aviation (DGCA) in association with the airport authorities, airlines and municipal and health authorities periodically carry out joint surveys of the areas surrounding major airports to identify the sources of bird attraction, suggest remedial measures and detect instances of violation of laws and regulations.

(iii) Prosecution is initated under Aircraft Rules against persons indulging in deskinning of dead animals and slaughtering of animals and disposal of garbage in the open which attract birds in the vicinity of the aerodrome.

(iv) Proper disposal of food wastes and garbage originating from flight kitchens and aircraft inside the aerodrome is ensured.